भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3046
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन

†3046. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, सराहनीय प्रगति हासिल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर में अपर्याप्त सीवेज उपचार अवसंरचनात्मक क्षमता और फकल स्लज प्रबंधन प्रौद्योगिकी की कमी का आकलन किया है,
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) उक्त क्षेत्रों में फकल स्लज प्रबंधन की समस्या के समाधान और सीवेज उपचार अवसंरचना में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): एसबीएम (जी) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के अनुसार, देश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 2.10.2019 से 04.08.2025 तक 11.91 करोड़ व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है। इन व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों से, मध्य प्रदेश में एसबीएम (जी) के तहत 77.64 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

(ख) से (घ): मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मलीय गाद की स्थिति का मूल्यांकन किया है और जहां व्यवहार्य हो, वहां शहरी अवसंरचना वाले गांवों का मानचित्रण करके जिला मलीय गाद प्रबंधन (एफएसएम) योजना बनाई है तथा कटनी

और पन्ना जिलों में आवश्यकता के अनुसार नए ग्रामीण मलीय गाद शोधन संयंत्रों (एफएसटीपी) की योजना बनाई है। गांवों में एफएसएम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कटनी और पन्ना प्रत्येक जिले में 1 एफएसटीपी के निर्माण की योजना बनाई गई है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश भर के 500 चयनित शहरों में वर्ष 2015 में शुरू किया गया अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में मूलभूत शहरी अवसंरचना के विकास पर केंद्रित था। देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में वर्ष 2021 में अमृत 2.0 शुरू किया गया, जो शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने पर केंद्रित है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के तहत प्रमुख ध्यान क्षेत्रों में शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क में से परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है।

अमृत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 121.57 करोड़ रुपये की लागत से कुल 02 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं (24.5 एमएलडी क्षमता) शुरू की गई हैं। अमृत 2.0 के तहत, अब तक, राज्य ने खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 220 करोड़ रुपये की 02 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं (39.59 एमएलडी क्षमता) शुरू की हैं।

*****